राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 293

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, मंगलवार, 31 मार्च 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 14

इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू भी क्वारंटाइन में

>> 11

कोरोना मीटर

(स्रोत : वर्ल्डोमीटर्स डॉट इंफो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

	विश्व	अमेरिका	इटली	भारत	(24 मार्च)	दिल्ली
कुल केस	7,38,987	1,42,793	97,689	1225	476	97
मौतें	35,013	2,490	10,779	37	9	2
स्वस्थ हुए	1,56,317	4,562	13,030	31	24	5

भारत के प्रमुख राज्य

राज्य	केस	मौतें
केरल	234	1
महाराष्ट्र	220	8
उत्तर प्रदेश	85	0
कनार्टक	83	3
तेलंगाना	70	7
गुजरात	70	5
राजस्थान	69	0
तमिलनाडु	50	0
अन्य	247	13

शाम 11 :45 बजे तक

अन्य प्रमुख देश

देश	स्पेन	चीन	जर्मनी
केस	85,195	81,470	63,079
मौतें	7,340	3,304	545

नोट : कोरोना से प्रभावित लोगों के संदर्भ में आंकड़े उल्लिखित दो सोतों के अतिरिक्त जागरण न्यूज नेटवर्क के रूप में अन्य माध्यमों से भी लिए गए हैं। अत : तालिका तथा दैनिक जागरण के इस अंक में प्रकाशित सामग्री में आंकड़ों का अंतर संभव है।

तब्लीगी मरकज में शामिल छह की तेलंगाना में मौत

चिंता ▶ लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन में आयोजन में हुए थे शामिल

दिल्ली में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1600 को क्वारंटाइन किया गया

जेएनएन, नई दिल्ली

लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी मरकज में शामिल छह लोगों की सोमवार को तेलंगाना में मौत हो गई। ये सभी कोरोना वायरस से संक्रमित थे। तेलंगाना सरकार ने इसकी पुष्टि की है। राज्य सरकार के बयान के मुताबिक, इन सभी ने दिल्ली में आयोजित मरकज में भाग लिया था और इसके बाद तेलंगाना लौटे थे। इनमें से दो की मौत गांधी अस्पताल में हुई और चार अन्य की निजी अस्पतालों में जान गई।

इस बीच, दिल्ली में मरकज से जुड़े 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 228 संदिग्ध मरीज भी दिल्ली के दो अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। इनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इस तरह से कुल 252 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मरकज से जुड़े कोरोना पीड़ित इंडोनेशिया, मलेशिया व जापान भी गए थे। वहां से लौटने के बाद इनमें से कई लोग तेलंगाना, तमिलनाडु व अंडमान गए थे। इस तब्लीगी मरकज में शामिल 1600 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। निजामुद्दीन में क्वारंटाइन किए गए जिन लोगों में बुखार, खांसी व सांस की परेशानी जैसे लक्षण विकसित हो रहे हैं, उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस बीच मरकज के दो मौलाना के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एफआइआर दर्ज करने को कहा है।

करीब 102 लोग सोमवार को भी लोकनायक व राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराए गए। राजीव गांधी अस्पताल में पिछले तीन दिनों में कुल 99 लोग भर्ती कराए जा चुके हैं। 28 मार्च को 31 लोग भर्ती कराए गए थे, जिनमें से 18 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाकी मरीजों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं लोकनायक अस्पताल में पिछले दो दिनों में निजामुद्दीन से 153 लोग भर्ती कराए गए हैं। इसी के साथ यहां भर्ती संदिग्ध मरीजों की संख्या 174 हो गई है। इसमें से 64 मरीजों को सोमवार को डीटीसी बस से ले जाकर लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

तब्लीगी जमात के इस मामले ने दिल्ली में कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को बढ़ाने का काम किया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के एलान के बाद दिल्ली और अन्य राज्यों के लोगों की अपने घरों को लौटने की कोशिश के चलते एहतियाती उपाय विफल होने का खतरा पहले ही उभर आया था। मरकज में शामिल हुए लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में लौटे हैं। मरकज से लौटकर जम्मू-कश्मीर जाने वाले सोपोर निवासी 65 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग की 26 मार्च को मौत हो चुकी है। इस लापरवाही ने कश्मीर में चिंता बढ़ा दी है।

हजरत निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज में जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों को बस में बैठाकर क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। जागरण

मरकज ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें : राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच निजामुद्दीन में लॉकडाउन के दौरान आयोजित हुए तब्लीगी मरकज के कारण इलाके के हजारों लोग मुसीबत में आ गए हैं। इस मरकज में करीब डेढ़ हजार लोग शामिल हुए थे। इनमें चीन, यमन, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, इंग्लैंड के भी 100 से अधिक लोग मौजूद थे। दक्षिणी-पूर्वी दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि मरकज के आयोजकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।

इस्लाम धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए दिया जाता है प्रशिक्षण : यहां इस्लाम धर्म के प्रचार-प्रसार व सुधार के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। एक समय में इसमें करीब डेढ़ हजार लोग शामिल होते हैं। 15 मार्च के बाद भी यहां विदेशी मरकजी आते रहे। जिस समय लॉकडाउन हुआ, उस सयम यहां 1500 लोग मौजूद थे।

और नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन

कैबिनेट सचिव बोले ▶ 21 दिन से आगे बढ़ाने की बातें गलत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 21 दिनों से आगे एक हफ्ता और बढ़ाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने साफ कहा है कि लॉकडाउन को 14 अप्रैल से आगे एक सप्ताह के लिए और बढ़ाए जाने संबंधी खबरें फर्जी हैं। सरकार की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को दोहराया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने घरों और गांवों को लौट रहे लोगों को रोककर उनके ठहरने और खाने-पीने के लिए जिलाधिकारियों (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को निजी तौर पर जिम्मेदार बनाएं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया विंग प्रेस इंफॉरमेशन ब्यूरो ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के हवाले से बयान जारी कर लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाए जाने का दावा करने वाली खबरों को गलत करार दिया। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट सचिव ने लॉकडाउन अवधि बढ़ाए जाने संबंधी समाचारों पर आश्चर्य प्रकट करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार की इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

इसी के साथ केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से अपने घरों और गांवों को लौट रहे लोगों को रास्तों में रोककर उनके ठहरने, खाने-पीने के इंतजाम करने और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की बात दोहराई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गृह सचिव ने राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के चेयरमैन के तौर पर रविवार को ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि अपने घर व गांव लौट रहे लोगों के ठहरने और खाने-पीने की जिम्मेदारी निजी तौर पर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सौंपी जाए। इसके अलावा जो लोग अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं उन्हें मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की संख्या नहीं बताई।

लौट रहे लोगों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के मसले पर पुण्य सलिला ने कहा कि पुलिस को संवेदनशीलता के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में एक धार्मिक आयोजन में भीड़ जुटने की खबरों पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।

- गृह मंत्रालय ने दोहराया, लौट रहे लोगों के ठहरने व खाने-पीने की जिम्मेदारी डीएम-एसपी को दें राज्य
- जो लोग अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं उन्हें मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन किया जाना चाहिए

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। एएनआइ

लॉकडाउन बढ़ने की अफवाह ने बढ़ाया भय

सरकार में माना जा रहा है कि सोशल मीडिया में लॉकडाउन अवधि बढ़ाए जाने जैसी अफवाह ने लोगों में भय बढ़ाया। इसी वजह से भी वे अपने कार्यस्थल वाले ठिकानों को छोड़कर गांव-घरों की ओर कूच करने लगे। परिणामस्वरूप सड़कों पर जनसैलाब उमड़ने के साथ-साथ शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ गईं। साथ ही सरकार और प्रशासन के समक्ष उनकी आवाजाही और खाने-पीने के इंतजाम करने की चुनौती खड़ी हो गई। एक अफवाह ने लोगों को कोरोना के खतरे के बीच जान पर खेलते हुए पलायन के लिए मजबूर कर दिया।

11 समूहों ने शुरू किया कामकाज

लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में दवाओं, मेडिकल साजो-सामान, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व परिवहन सेवाओं का संचालन सुनिश्चित करने को 11 अधिकार प्राप्त समूहों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। 80 वरिष्ठ अधिकारियों को इनके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आइसोलेशन वार्ड में तब्दील होंगे रेलवे के पांच हजार कोच

नई दिल्ली : कोरोना से निपटने के लिए चीन ने वुहान में 10 दिनों में एक हजार बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल बनाया था। उसी तरह भारत भी कुछ दिनों में पांच हजार रेल कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करेगा। (पेज-4)

लॉकडाउन का असर : अब तक थमा है कोरोना वायरस का प्रसार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भारत में मरीजों की संख्या 100 से 1000 पहुंचने में लगे 12 दिन
- कई देशों में 12 दिनों में 100 से बढ़कर 8000 तक पहुंच गए मरीज
- अधिक संक्रमितों वाले हॉटस्पॉट पर सरकार की नजर
- देश में कोरोना वायरस अभी लोकल ट्रांसमिशन के दूसरे फेज में

लॉकडाउन से भले ही लोगों को परेशानी हो रही हो, लेकिन कोरोना वायरस के प्रसार की गति को यह काफी हद तक थामने में सफल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार, भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 100 से 1000 पहुंचने में 12 दिन लगे हैं। इसकी तुलना दुनिया के दूसरे विकसित देशों से करें, तो वहां 12 दिनों में संख्या 100 से बढ़कर आठ हजार तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा, इसे आगे बनाए रखने को सौ फीसद अलर्ट रहने व सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है।

लव अग्रवाल ने कोरोना के प्रसार की गति कम होने का श्रेय लॉकडाउन और दूसरे एहतियाती उपायों को देते हुए कहा कि जिन देशों ने समय पर एहतियाती कदम नहीं उठाए, उन देशों में यह बेकाबू होता गया। उनके अनुसार, सरकार की कोशिश कोरोना के फैलने का इंतजार करने के बजाय पहले ही इस पर पूरी तरह नियंत्रण करने की है और इसमें जनता के सौ फीसद सहयोग की जरूरत है। इसमें जरा भी कोताही अभी तक मिली सफलता पर पानी फेर सकता है।

अपने आंतरिक नोट में 'लिमिटेड कम्यूनिटी ट्रांसमिशन' शब्द के प्रयोग का गलत अर्थ निकाले जाने के प्रति सावधान करते हुए अग्रवाल ने कहा, कोरोना अभी तक भारत में लोकल ट्रांसमिशन के दूसरे फेज में ही है। यदि कम्यूनिटी ट्रांसमिशन का फेज शुरू हुआ तो सबसे पहले लोगों को इसकी जानकारी देंगे ताकि वे सतर्क हो सकें। उन्होंने कहा, जिस आंतरिक नोट का लिमिटेड कम्यूनिटी ट्रांसमिशन के सिलसिले में जिक्र किया जा रहा है, उसमें भी साफ लिखा है कि अभी तक मिले सारे मामले लोकल ट्रांसमिशन के हैं। कुछ मरीज जरूर बिना हिस्ट्री के सामने आए हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है और इसकी जांच अलग से की जा रही है। पूरे देश में लॉकडाउन बाद के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन हॉटस्पॉट पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे हॉटस्पॉट में उन अधिक जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को भी रखा गया है, जहां कोरोना के वायरस के फैलने की आशंका अधिक है।

अग्रवाल ने कहा कि ऐसे इलाकों के लिए विशेष रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। जिसमें एक-एक घर में जाकर लोगों की पड़ताल की जा रही है और जरा सा भी संदिग्ध होने पर उसकी जांच की जा रही है। ऐसे इलाकों के लिए विशेष एसओपी बना हुआ है और उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। हॉटस्पॉट के इलाके के बाहर में भी एक बड़े इलाके की पहचान बफर जोन के रूप में की जाती है। ऐसे बफर जोन में भी सभी पर खास नजर रखी जाती है और यदि किसी में सांस से संबंधित गंभीर बीमारी के लक्षण दिखते हैं, तो तत्काल उसकी जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि देश में कई इलाकों की हॉटस्पॉट के रूप में पहचान की गई है।

लॉकडाउन को लेकर सख्ती पेज>>00

छुट्टी मांगने पर हटाए गए गौतमबुद्ध नगर के डीएम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- मुख्यमंत्री की फटकार के बाद मांगा था तीन महीने का उपार्जित अवकाश
- शासन दे सकता है उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश

कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण चर्चा में आए उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह को शासन ने पद से हटा दिया है। आपदा घोषित की गई कोविड-19 महामारी के दौरान दायित्व से मुंह मोड़ने और छुट्टी पर जाने के उनके अनुरोध को ठुकराते हुए शासन ने उन्हें राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया है। नियोजन विभाग में विशेष सचिव पद पर तैनात 2007 बैच के आइएएस अफसर सुहास एलवाई को गौतमबुद्ध नगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

प्रदेश में कोरोना के सर्वाधिक मामले नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठकों में इस पर चिंता जताई थी और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को वहां कैंप करने का निर्देश दिया था। सोमवार को सीएम खुद गौतमबुद्ध नगर पहुंचे और कोरोना से निपटने के उपायों की समीक्षा की। काम में ढिलाई बरतने व जिम्मेदारी दूसरे के पाले में डालने पर उन्होंने जिलाधिकारी बीएन सिंह को फटकार लगाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद सिंह ने मुख्य सचिव आरके तिवारी को प्रार्थना पत्र भेजकर खुद को तीन माह का उपार्जित अवकाश दिए जाने और जिलाधिकारी के पद पर किसी अन्य अधिकारी की तैनाती का अनुरोध किया।

कोरोना को केंद्र व राज्य सरकारों ने आपदा घोषित किया है। आपदाकाल में जिलाधिकारी की ओर से छुट्टी मांगे जाने को शासन ने गंभीरता से लिया और उन्हें वहां से हटाकर राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, शासन उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दे सकता है। बीएन सिंह की जगह गौतमबुद्ध नगर के डीएम बनाए गए सुहास एलवाई साफ-सुथरी छवि के अफसर माने जाते हैं। बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी सुहास पैरालिंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक भी जीत चुके हैं। इससे पहले वह प्रयागराज और आजमगढ़ के जिलाधिकारी रह चुके हैं। (पेज-5 भी देखें)

बीएसएनएल के आठ करोड़ ग्राहकों को मुफ्त टॉकटाइम

नई दिल्ली : कोरोना संकट की इस घड़ी में बीएसएनएल ने प्री-पेड ग्राहकों को राहत दी है। बीएसएनएल के सभी प्री-पेड सिम बिना किसी रिचार्ज के 20 अप्रैल तक मान्य रहेंगे। इन प्री-पेड ग्राहकों को 10 रुपये की मुफ्त आउटगोइंग कॉल की भी सुविधा मिलेगी। (पेज-3)

पीपीई, एन-95 और वेंटिलेटर जुटाने में लगा भारत

नई दिल्ली : सरकार ने कोरोना से जंग के दौरान उपयोग में आने वाले उपकरणों की उपलब्धता का हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में कितने पीपीई, एन-95 और वेंटिलेटर मौजूद है और कैसे इनका और इंतजाम किया जा रहा है। (पेज-6)

भारत ने अब तक जीडीपी के 4.3 फीसद का दिया पैकेज

नई दिल्ली : अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए बूस्टर डोज देने में भारत भी पीछे नहीं है। फरवरी से लेकर अब तक रिजर्व बैंक और सरकार की तरफ से नौ लाख करोड़ से अधिक के वित्तीय पैकेज की घोषणा की जा चुकी है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 4.3 फीसद के बराबर है। (पेज-10)

निश्चिंत रहें, पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार

आप सब इससे अवगत ही होंगे कि प्रख्यात डॉक्टर, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ आदि बार-बार यह कह रहे हैं कि अखबारों से कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का कोई खतरा नहीं है। आप पूरी तरह निश्चिंत होने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके खुद देख सकते हैं कि आपका प्रिय दैनिक जागरण समाचार पत्र कितने सुरक्षित तरीके से छपकर आपके हाथों में पहुंचता है। सतर्कता और सजगता की यह प्रक्रिया हम हर दिन-हर क्षण अपनाते हैं, क्योंकि आपकी तरह हम भी कोरोना को परास्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रतिबद्धता को और प्रबल करने के लिए यह आवश्यक है कि आप समाचारों के सबसे विश्वसनीय स्रोत से जुड़े रहें। आपकी तरह हमें भी यह भरोसा है कि हम यह जंग जीतेंगे।

हेल्पलाइन नंबर

कोरोना से जुड़ी सही जानकारी देने के लिए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों को मोबाइल में सुरक्षित करके कोई भी प्रामाणिक सूचना पाई जा सकती है। कृपया नंबर दर्ज करके वाट्सएप पर सिर्फ नमस्कार का संदेश भेजें। तुरंत एक मेन्यू आएगा, जिसके अनुसार वांछित जानकारी ली जा सकती है।

who:+41 798931892

mygov : +9190131515 15

मोदी बोले, अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा देश ● पेज 3

सेहत से खिलवाड़, यात्रियों पर केमिकल की बौछार ● पेज 4

क्या गली, क्या गांव, चौकसी हर ठांव (ग्राउंड रिपोर्ट) ● पेज 5

सरोकार

90 दिनी फूड चैलेंज! जितनी भूख उतना भोजन...

कोलकाता : भोजन की बर्बादी रोकने को रिटायर्ड कर्नल जीवन कुमार सिंह पेश कर रहे 90 दिनों का अनूठा फूड चैलेंज। उन्होंने पूरे देश को इस मुहिम से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। प्रतिदिन जुड़ रहे डेढ़ हजार लोग। (पेज-13)

जागरण विशेष

शाबाश शंभली! सूझबूझ और हिम्मत से दी कोरोना को मात

नोएडा : उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी शंभली ने मजबूत इरादों से कोरोना को हराकर घर वापसी कर ली है। बताती हैं कि अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और स्टाफ ने महसूस नहीं होने दिया कि बीमार थी। (पेज-13)

राहत

आठ डिग्री सेल्सियस तापमान कोरोना के पनपने की आदर्श स्थिति, बढ़ते तापमान के साथ घट रही कोविड-19 वायरस की संख्या, जीन वैज्ञानिकों का दावा, महामारी से पूर्व की जा सकती है भविष्यवाणी

23 डिग्री सेल्सियस पर मरे आधे कोरोना वायरस

हिमांशु अस्थाना, वाराणसी

विश्व का कोना-कोना कोरोना वायरस से भयभीत है लेकिन, भारत में तेजी से बढ़ रहा तापमान राहत की खबर लेकर आने वाला है। बीएचयू के जीन वैज्ञानिक प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे और दिल्ली स्थित आइसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) के डॉ. प्रमोद कुमार ने अपने लैब में शोध से यह निष्कर्ष निकाला है। जीन वैज्ञानिकों ने लैब में शून्य से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक कोविड-19 की हरकत का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि शून्य से 23 डिग्री सेल्सियस तक आते-आते कोविड-19 वायरस की संख्या आधी हो गई थी।

प्रो. चौबे के मुताबिक, यह शोध जनता और प्रशासन को राहत देने वाला है। गंगा के मैदानी इलाके में तापमान अधिकतम 30 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे आधी समस्या समाप्त हो गई है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। तापमान के आधार पर कोरोना वायरस के वजूद का गणितीय आकलन किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि तूफान, चक्रवात, बाढ़ और मौसम के दौरान जान बचाने व राहत को लेकर जैसे देश में भविष्यवाणी की जाती है, उसी तरह कोरोना को लेकर महामारी की आशंका से पूर्व सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है।

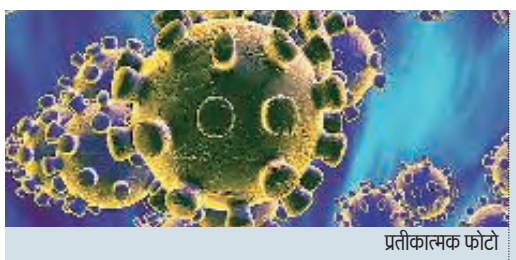

प्रतीकात्मक फोटो

बीएसएल-4 लैब में किया गया विश्लेषण

प्रो. ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक, बीजिंग द्वारा निर्धारित वायरस के आरएनए सीक्वेंसिंग को आर प्रोग्रामिंग की मदद से तापमान के साथ महामारी का कंप्यूटर सिमुलेशन किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट डॉ. प्रमोद को भेजी जाती है। यहां खास प्रकार की बीएसएल-4 लैब में विभिन्न तापमान पर वायरस की हरकतें नोट कर उन्हें कंप्यूटर सिमुलेशन के आंकड़े से मेल कराया जाता है। दोनों आंकड़े 99 .99 फीसद मिल जाते हैं तो कोरोना के घटते स्तर की पुष्टि हो जाती है।

20 दिनों में मिली सफलता

डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि इस शोध में प्रो. चौबे के साथ वह पिछले 20 दिनों से लगे थे। अपने शोध में उन्होंने यह भी पाया कि आठ डिग्री सेल्सियस तापमान कोविड-19 के पनपने की सबसे आदर्श स्थिति है। इस खोज के आधार पर दोनों जीन वैज्ञानिकों को हॉर्वर्ड, कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड सरीखे वैश्विक संस्थानों के वैज्ञानिकों की कंसोर्टियम में भी शामिल किया गया है।

लॉकडाउन के बीच विशेष अंदाज में चला ओडिशा विस का विशेष सत्र

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : लॉकडाउन के बीच सोमवार को ओडिशा विधानसभा का विशेष सत्र खास अंदाज में चला। ओडिशा के इतिहास में पहली बार विधानसभा की कार्यवाही सदन के बाहर लोकसेवा भवन में हुई और शायद पहली ही बार है कि बिना किसी विरोध के व्यय बिल पारित हो गया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डेढ़ लाख करोड़ का व्यय बिल सोमवार को सर्वसम्मति से पारित करने के साथ ही 38 विभागों की व्यय मांगों का भी गिलोटिन के जरिए सदन ने अनुमोदन किया है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर बजट अधिवेशन के दूसरे चरण को सीमित किया गया था। मंगलवार को पारित होने वाले व्यय बिल को एक दिन पहले ही पारित कर दिया गया।

कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आया था विधानसभा कर्मचारी पेज>>5

अगले साल 23 जुलाई से आयोजित किए जाएंगे टोक्यो ओलंपिक

- टोक्यो आयोजन समिति के प्रमुख योशिरो मोरी ने घोषित की नई तारीख

टोक्यो, एएफपी : कोरोना के चलते स्थगित किए गए टोक्यो ओलंपिक खेल अब अगले साल 23 जुलाई से आयोजित किए जाएंगे। पहले इनका आयोजन इस साल 24 जुलाई से नौ अगस्त तक होना था।

टोक्यो आयोजन समिति के प्रमुख योशिरो मोरी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'अब ओलंपिक खेल अगले साल 23 जुलाई से आठ अगस्त तक आयोजित होंगे, जबकि पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से पांच सितंबर तक होंगे।' इससे कुछ घंटे पहले ही मोरी ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) इस सप्ताह नई तारीखों पर फैसला लेगी। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इन खेलों को स्थगित करना पड़ा था। आइओसी और जापान सरकार लगातार दोहराते रहे कि खेल तय समय पर होंगे, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच खेल महासंघों और खिलाड़ियों के दबाव में उन्हें फैसला लेना पड़ा। ऐसी भी अटकलें थीं कि खेलों को अगले साल फरवरी में कराया जाए लेकिन उस समय कई फुटबॉल लीग और उत्तर अमेरिकी खेल लीग का आयोजन होता है।

मोरी ने कहा था कि नई तारीखों पर खेलों के आयोजन की लागत काफी अधिक होगी। यह लागत अरबों डॉलर बढ़ जाएगी और इसका बोझ जापान के करदाताओं पर पड़ेगा।

जापान आधिकारिक तौर पर ओलंपिक की मेजबानी पर 12.6 अरब डॉलर (948 अरब रुपये) खर्च कर रहा है। जापानी सरकार के एक ऑडिट ब्यूरो ने कहा, लागत इसकी दोगुनी है। मुतो ने कहा, हमारी कोशिश जुलाई-अगस्त में ओलंपिक कराने की थी जिससे अन्य टूर्नामेंटों पर असर नहीं पड़े।